



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 1996/पौष 18, 1917

No. 18]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1996/PAUSA 18, 1917

मानव संसाधन] विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1996

क. अ. 20(ग्र.)—परियोजना अनुमोदन समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार के दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 की प्रधिसूचना संख्या एफ-9-18/94-ए.ई. 1 के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की एक उप समिति गठित की गई थी तथा भारत सरकार के दिनांक 26 जून, 1988 के संकल्प संख्या एफ. 9-5/87-ए.ई. 1 (जिसे आगे चल कर दिनांक 13-12-94 की संकल्प संख्या एफ. 9-18/94-ए.ई. 1 द्वारा संशोधन किया गया) के पेय 4 में प्रवस्त्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना अनुमोदन समिति का पुनर्गठन किया जाय। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

1. सचिव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

3. विसीय मलाहृकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग	सदस्य
4. श्री सत्येन मैत्रा अवैतनिक निदेशक भूगोल समाज सेवा सीन 1/6, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	सदस्य
5. डा. बीना वाम दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, दिल्ली	सदस्य
6. डा. डेनिजल सल्याना ठाठा सामाजिक विज्ञान संस्थान सियोन—द्राम्बे रोड, देवनार, बम्बई-400088	सदस्य
7. निदेशक (संपूर्ण साक्षरता प्रभियान) शिक्षा विभाग	सदस्य-सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

राष्ट्रीय भारता मिशन के अन्तर्गत सभी योजनाओं से संबंधित परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।

संबंधित राष्ट्रीय सरकारों के संबंधित शिक्षा संचयों तथा प्रोड शिक्षा निवेशकों को जिन्हें संदूर्जन/उत्तर सामरता अभियानों के प्रस्तावों पर विचार करने का वायित्व सौंपा गया है, उन्हें इसकी विशेष [बैठक में भाग लेने के लिए सबस्थ रूप में भी सहयोगित किया जाएगा।

गैर-सरकारी सबस्थों के मनोनीत व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 31-3-97 की अवधि तक परियोजना अनुमोदन समिति में कार्य करेंगे।

परियोजना अनुमोदन समिति के गैर-सरकारी सबस्थ भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा तथा वैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. एफ-9-18/94-ए.ई.-1]
भास्कर चट्टर्जी, संबूद्ध समिति

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 1996

S.O. 20(E).—On expiry of the term of the Project Approval Committee, a sub-committee of the Executive Committee of the National Literacy Mission Authority constituted vide Government of India Notification No. F-9-18/94-AE.I dated the 15th December, 1994 and in exercise of the powers delegated in para 4 of Government of India Resolution No.F. 9-5/87-AE.I, dated 26th June, 1988 (modified further vide Resolution No. F-9-18/84-AE.I, dated 13-12-94) it has been decided to reconstitute the Project Approval Committee with the following members :—

1. Secretary Chairman
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
New Delhi.
2. Joint Secretary and Director General of Vice Chairman
NLM

3. Financial Adviser Member
Ministry of Human Resource
Development
Department of Education
4. Shri Satyen Mitra Member
Honorary Director,
Bengal Social Services League
1/6, Raja Dinendra Street
Calcutta-700009
5. Dr. Veena Das Member
Delhi School of Economics
Delhi.
6. Dr. Denzil Saldhana Member
Tata Institute of Social Sciences
Sion-Trombay Road
Deonar, Bombay-400088
7. Director (TLC) Member
Department of Education
Ministry of Human Resource
Development.
New Delhi.

The Project Approval Committee is vested with full powers to clear the project proposals in respect of all schemes under the National Literacy Mission.

The concerned Education Secretaries and the Directors of Adult Education of the respective State Governments whose proposals for total/post literacy campaigns are considered would also be co-opted as members in the particular meeting.

The non-official nominees would serve on the Project Approval Committee for a period upto 31-3-97 from the date of issue of this Notification.

The non-official members of the Project Approval Committee shall be entitled to travelling and daily allowances as per the rules of Government of India.

[No. F-9-18/94-AE.I]

BHASKAR CHATTERJEE, Jt. Secy.